>

Title: Ongoing countrywide strike of the National Postal Employees.

SHRI N.N. KRISHNADAS (PALGHAT): Sir, the postal employees of the country are on strike yesterday onwards all across the country. Their demand is that lakhs and lakhs of ED employees of the Postal Department should be considered as Government employees.

In this regard, there was a Natrasjmurthy Committee, which was constituted by the Government. Its Report has been submitted to the Government. But all the recommendations of this Committee are against the interests of the employees of the Postal Department. Only yesterday onwards, across the country, the postal movements are at standstill.

Therefore, I would urge upon the Government to immediately intervene in this matter and call for a conciliation meeting with the leaders of the postal employees and settle the issue in favour and interest of the postal employees of the country.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा कि देश के लाखों डाकघरों में डाकसेवाएं अस्त-व्यस्त हो गयी हैं। 17 दिसंबर से साढ़े तीन लाख ग्रामीण डाक सेवक हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप गांवों में डाकसेवाएं अस्त-व्यस्त हो गयी हैं। जगह-जगह से खबरें आ रही हैं कि डाक नहीं पहुंच पा रही है और डाकघरों में जो छोटी-छोटी बचत वगैरह के काम होते थे, तीन से पांच घण्टे तक का काम, ठप हो गए हैं।

अध्यक्ष जी, जब आप संचार संबंधी स्थायी समिति के सभापति थे, आपने डाक विभाग के कल्याण के लिए बहुत सी बातें सोची थीं। उसी सन्दर्भ में भारत के ग्रामीण क्षेत्र में 74.2 प्रतिशत जनता, उसमें 1,27, 823 शाखा डाकघर हैं, उन सभी में काम ठप हो गया है और उनमें काम करने वाले लगभग 3,10,296 ग्रामीण डाकसेवक हैं। इन ग्रामीण डाकसेवकों के लिए पांचवें वेतन आयोग के बाद तलवार समिति गठित की गयी थी, लेकिन उस समिति की सिफारिशों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। अब छठा वेतन आयोग आ चुका है। इन ग्रामीण डाकसेवकों को सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सर्वेंट माना है, लेकिन अभी तक इनको सिविल सर्वेंट्स के समान सुविधाएं जैसे मकान किराया भत्ता, ग्रेच्युटी, पेंशन, वेतनमान और वेतनवृद्धि आदि से वंचित रखा गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र की डाकसेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अविलम्ब इन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर बातचीत करे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हैं, लेकिन थोड़ा धीरे बोलिए।

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदय, इस तरह से लम्बे समय से ऐसे डाककर्मियों के साथ अत्याचार और शोषण हो रहा है। एक ओर असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है और दूसरी तरफ संगठित क्षेत्र के इन साढ़े तीन लाख ग्रामीण डाकसेवकों, जो गांवों में रात-दिन, पांच से सात घण्टे तक काम करने वाले लोग हैं, की कोई सुनवाई नहीं हो रही है।[R9]

इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वह माननीय प्रधान मंत्री और सम्बन्धित संचार मंत्री जी तक हमारी आवाज को पहुंचाने का कष्ट करें ताकि उनकी हड़ताल खत्म हो। इसलिए सरकार को उनके प्रतिनिधियों के साथ मिलकर समस्या का समाधान करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने नटराज मूर्ति कमेटी गठित की।

अध्यक्ष महोदय: क्या इसका भी इससे सम्बन्ध है?

प्रो. रासा सिंह रावत : उस कमेटी ने इन कर्मियों के जले पर नमक छिड़कने वाली बात कर दी। उस कमेटी ने इनके वेतनमानों में कमी और रिटायरमेंट की आयु सीमा घटाने की सिफारिश की। इससे इन साढ़े तीन लाख ई.डी. कर्मचारियों में काफी आक्रोष व्याप्त हो रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह अविलम्ब इस हड़ताल को खत्म कराए और ग्रामीण डाक व्यवस्था को फिर से सुचारू रूप से चलाने हेतु कार्य में डाक सेवक कर्मचारियों की मांगें अविलम्ब स्वीकार करें।

अध्यक्ष महोदय:

श्री राम कृपाल यादव, श्री पी.एस. गढवी, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, श्री गणेश सिंह, श्रीमती सुशीला बंगारु और श्री किशन सिंह सांगवान भी इस विषय के साथ एसोसिएट करते हैं।

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Are you associating?

ADV. SURESH KURUP (KOTTAYAM): I have given notice.

MR. SPEAKER: Let us see.